

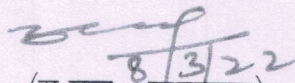
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर
क्रमांक: सामान्य/क्रय/मु.भं./05/2022-23/ 79062-67 दिनांक: 09-3-2022

खुली बोली आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के सम्पूर्ण परिसर में बगीचा (लॉन) लगाना एवं समस्त पेड़ पौधों का रख-रखाव का कार्य करने हेतु तथा महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर के कार्यालय के समस्त परिसर, कमरों तथा टॉयलेटों की साफ सफाई व्यवस्था हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं। बोली दिनांक 16/03/2022 को दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोली जायेगी। बगीचे/कार्यालय परिसर का अवलोकन, अन्य शर्तें एवं बोली फार्म कार्यालय समय में प्राप्त की/देखी जा सकती हैं। बोली की अन्य विशिष्टियां व शर्तें सूचना एवं कारागार विभाग की बैबसाइट "www.rajprisons.nic.in" एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल "www.home.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध हैं। बोली फार्म हेतु निर्धारित राशि नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चेक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।


क्र. सं.	वस्तु का नाम	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क
1.	सम्पूर्ण परिसर में बगीचा (लॉन) लगाना एवं समस्त पेड़ पौधों का रख-रखाव का कार्य हेतु	02.50	5000/-	200/-
2.	कार्यालय के समस्त परिसर, कमरों तथा टॉयलेटों की साफ सफाई व्यवस्था हेतु	02.50	5000/-	200/-

UBN:-JL D2122SSRC/14


(यू.एल. छानवाल)
महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य.....।
3. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 7 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावे।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. नोटिस बोर्ड मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर पर चस्पा हेतु।
6. रक्षक पत्रावली।


महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट "अ"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्वालीफाईंग बोली प्रारूप
तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के सम्पूर्ण परिसर में बगीचा (लॉन) लगाना एवं समस्त पेड़ पौधों का वार्षिक रख-रखाव किये जाने एवं साफ सफाई व्यवस्था हेतु बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/ठेकेदार का नाम व डाक का पता एवं दूरभाष संख्या :-----

3. किसको संबोधित की गई। महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर।
4. संदर्भ:- सामान्य/क्रय/मु.भं./05/2022-23/.....दिनांक:.....
5. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रुपये -----नकद रसीद संख्या-----दिनांक ----- /डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक संख्या ----- दिनांक ----- के द्वारा जमा कर दी गयी है।
6. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ---
-----जो (बैंक का नाम) -----
----- पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या ----- चालान संख्या----- दिनांक ----- राशि रुपये ----- संलग्न है।
7. हम महानिदेशालय कारागार, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या सामान्य/क्रय/मु.भं./05/2022-23/-----दिनांक ----- में वर्णित सभी शर्तों मय परिशिष्ट "अ" "ब" "स" व एनेक्चर "A" "B" "C" "D"(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) तथा दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. आदेश जारी करने की दिनांक से कार्यालय परिसर के समस्त बगीचा (लॉन) की उचित देखभाल एवं कार्यालय की समस्त परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था शुरू करनी होगी।
9. फर्म के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है।
10. उद्धृत की गई दरें 31 मार्च 2023 तक के लिये विधिमान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
11. फर्म/ठेकेदार का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. बोली दरें संलग्न निविदा प्रपत्र (वित्तीय बिड़) में ही प्रस्तुत की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
निविदा - प्रपत्र (वित्तीय बिड)

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर पर स्थित समस्त बगीचे (लॉन) का वार्षिक रख-रखाव के कार्य एवं समस्त परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था की वित्तीय निविदा प्रपत्र।

1. बोलीदाता फर्म/ठेकेदार का नाम व पूर्ण पता:-.....
.....
.....
दूरभाष संख्या..... मोबाईल नं..
.....

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित वार्षिक राशि (समस्त टैक्स/चार्जेज सहित)	
		अंको में रूपये	शब्दों में रूपये
1.	महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के सम्पूर्ण परिसर में बगीचा (लॉन) लगाना एवं समस्त पेड़ पौधों का वार्षिक रख-रखाव का कार्य करने हेतु.		
2.	महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर के कार्यालय के समस्त परिसर, कमरों तथा टॉयलेटों की साफ सफाई व्यवस्था हेतु		

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:.....

पूर्ण पता.....

.....

9

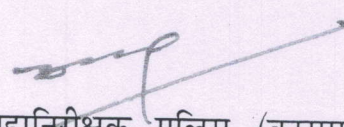
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
-: बोली की शर्तें :-
(बगीचा (लॉन) वार्षिक रख-रखाव की शर्तें)

1. महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के सम्पूर्ण परिसर में बगीचा (लॉन) लगाना एवं समस्त पेड़ पौधों का वार्षिक रख-रखाव का कार्य 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा जो कि 03 माह तक बढ़ाई भी जा सकेगी।
2. सम्पूर्ण परिसर में लगे हुए लॉन एवं बगीचा में प्रतिदिन पानी देना, बगीचे की सफाई, घास उगाई, कटाई व सभी प्रकार की देखभाल व अन्य जगहों पर भी लॉन लगाने का कार्य किया जाना।
3. बगीचे में स्थित पेड़ों की कटाई-छटाई की जावेगी।
4. महानिदेशालय कारागार परिसर में पूर्व स्थित बाग-बगीचा का रख-रखाव एवं मोटर साईकिल स्टेण्ड व लेखा शाखा के पास नया बगीचा का रख-रखाव करना होगा। कम से कम दो कार्मिक को आवश्यक रूप से कार्य हेतु लगाना होगा जो प्रतिदिन 8.00 घण्टे उपस्थिति देकर पूर्ण कार्य दिवस में कार्य करेंगे।
5. परिसर में नये लॉन के विकास हेतु पोधारोपण करना, खाद, पानी आदि संबंधित कार्य संचित करना होगा।
6. बगीचे के अलावा कार्यालय में स्थित पेड़, पौधों एवं गमलों की कटाई-छटाई, पेड़ों के पत्ते, कचरा साफ-सफाई व देखभाल करनी होगी।
7. भुगतान मासिक अनुपातिक आधार पर महानिदेशालय द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने के सत्यापन पर बिल कार्ष कार्यालय से पारित होने पर देय होगा।
8. सफल बोलीदाता को इस कार्य हेतु विभाग के साथ निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा तथा नियमानुसार कार्य निष्पादन राशि 2.5% आदेश प्राप्त होने के सात दिवस की अवधि में जमा करानी होगी जो कि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवायी जा सकती है।
9. सफल बोलीदाता द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं करने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी कार्य निष्पादन राशि जब्त करते हुए, उनकी रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवा लिया जायेगा।
10. बोलीदाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
11. बगीचा (लॉन) का वार्षिक रख-रखाव कार्य का वार्षिक कुल मूल्य राशि 2.50 लाख तक का अनुमान है। जिसमें कमी एवं वृद्धि हो सकती है।
12. बोली प्रतिभूति राशि- (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। (ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज., जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:-
(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद- शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप- 103- प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई-ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या
(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।

13. बगीचे (लॉन) के देखरेख में उपयोग होने वाले मशीन, औजार संयंत्र बोलीदाता के होंगे। आवश्यकतानुसार खाद एवं कीटनाशक इत्यादि इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
14. बगीचे के देखरेख के दौरान किसी प्रकार की राज्य सम्पत्ति की हानि की वसूली बिना सूचना के भुगतान बिल से कर ली जावेगी।
15. बोली दरें संलग्न निविदा प्रपत्र (वित्तीय बिड़) में ही प्रस्तुत की जावेगी।
16. बोली के साथ बोली दस्तावेज के समस्त पत्रादि यथा एनेक्चर "A" "B" "C" "D" आदि हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न प्रस्तुत करने होंगे।
17. कार्यालय में स्थित गमलों की देखभाल का भी दायित्व बोलीदाता का होगा।
18. बोलीदाता द्वारा नियुक्त कार्मिक का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी व कार्यालय में नियुक्त कार्मिक का पूर्ण पता, दूरभाष उपलब्ध करवाना होगा।
19. कार्य करने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का मुवावजा देय नहीं होगा।
20. महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर के सम्पूर्ण परिसर(सामने का बगीचा, लेखा शाखा के पास का गार्डन व अन्य खाली पड़ी जगहों पर) दूब लगाने व पेड़ पौधे लगाने, उनकी प्रतिदिन देख-रेख, पानी देना, प्रत्येक सप्ताह दूब कटिंग, प्रत्येक सप्ताह सीजन के अनुसार फूलवारी लगाने, पेड़ों की कटाई-छंटाई, पेड़-पौधों के पत्ते उठाने, लॉन व पेड़ों के नीचे पूर्ण साफ-सफाई आदि कार्य का वार्षिक रख-रखाव का कार्य।
21. कार्य हेतु उपस्थित कार्मिकों की पंजिका संधारण की जावेगी, जिसमें उपस्थिति तथा प्रतिदिन किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जावेगा।
22. प्रतिमाह का बिल भुगतान गठित कमेटी द्वारा संतोषप्रद कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।
23. सफल बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक के उपस्थित नहीं होने अथवा उपयुक्त साफ-सफाई नहीं होने पर प्रतिदिन रूपये 200/- के हिसाब से जुर्माना कटौती की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर


महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

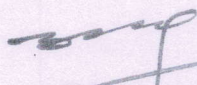
-: बोली की शर्त :-

(कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की शर्त)

1. कार्यालय में समस्त सफाई व्यवस्था की सेवाएँ प्रदान करने की अवधि दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी। जिसे विशेष परिस्थितियों में 03 माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. सफल बोलीदाता/बिडर के कार्मिक द्वारा महानिदेशालय कारागार के परिसर के सम्पूर्ण खुले भाग, कार्यालय के समस्त कक्षों, गैलेरियों, बरामदों, सीढ़ियों, शौचालयों व बाथरूमों की झाड़ू से सफाई कर फिनायल का पौछा रोजाना प्रातः कार्यालय खुलने से पूर्व लगाया जायेगा।
3. उक्त कार्य के लिए कम मे कम 02 कार्मिक लगाये जायेंगे। जिन्हे जो प्रातःकाल 7.00 बजे से साफ-सफाई व्यवस्था शुरू करनी होगी। जिसके लिए कार्मिकों को पाबन्द किया जाना है।
4. बोलीदाता/बिडर को वर्षा या अन्य किसी कारण से कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए पानी की निकासी करना एवं सफाई के दौरान एकत्रित कचरे को निर्धारित स्थान पर डालकर उसका निस्तारण करना होगा।
5. प्रत्येक कार्यालय दिवस एवं अवकाश दिवस में भी नियमित रूप से साफ-सफाई का कार्य किया जावेगा।
6. कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को समय-समय पर सफाई कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा उनके निर्देशों की सफल बोलीदाता/ठेकेदार को पालना करनी होगी।
7. सफल बोलीदाता/ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं आचरण का जिम्मा सफल बोलीदाता/ठेकेदार का होगा, अन्य किसी भी कारण से कर्मचारियों को क्षति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. भुगतान मासिक अनुपातिक आधार पर महानिदेशालय द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने के सत्यापन पर बिल कोष कार्यालय से पारित होने पर देय होगा।
9. सफल बोलीदाता/ठेकेदार को इस कार्य हेतु विभाग के साथ 500/- रुपये राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा तथा कार्यदेश की कुल वार्षिक लागत राशि के 2.5% के बराबर कार्य निष्पादन राशि आदेश प्राप्त होने के सात दिवस की अवधि में जमा करानी होगी जो कि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवायी जा सकती है।
10. सफल बोलीदाता द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं करने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी कार्य निष्पादन राशि जब्त करते हुए, उनकी रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवा लिया जायेगा।

11. बोलीदाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
12. साफ-सफाई कार्य का वार्षिक कुल मूल्य राशि 2.50 लाख तक का अनुमान है। जिसमें नियमानुसार कमी एवं वृद्धि हो सकती है।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी, जो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर के नाम ई-ग्रास चालान/शिडयूल्ड बैंक का बैंक डी.डी/बैंकर्स चैक आदि माध्यम से दी जायेगी।
14. बोली दरें संलग्न निविदा प्रपत्र (वित्तीय बिड़) में ही प्रस्तुत की जावेगी।
15. सफल बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी व कार्यालय में नियुक्त कार्मिक का पूर्ण पता, दूरभाष उपलब्ध करवाना होगा।
16. सफल बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्यों/अनुशासनहीनता से कार्यालय को होने वाली क्षति की वसूली सफल बोलीदाता/ठेकेदार को देय मासिक भुगतान राशि में से की जायेगी।
17. सफल बोलीदाता/ठेकेदार को समय-समय पर जारी केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा।
18. कार्य करने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी सफल बोलीदाता/ठेकेदार की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
19. सफल बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक के उपस्थित नहीं होने अथवा उपयुक्त साफ-सफाई नहीं होने पर प्रतिदिन रुपये 200/- के हिसाब से जुर्माना कटौती की जावेगी।
20. उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना का अभाव पाये जाने पर ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
21. सफाई के लिए आवश्यक सफाई सामग्री कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर


महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट-“स”

खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया:-** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. **बातचीत (Negotiation) :-**
 - (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:-
 - (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
 - (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
 - (ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्त न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।
3. **बोली की विधि मान्यता:-**

दरों की वैधता बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
4. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**
 - (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावों या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
 - (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
5. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :-** सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।
6. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) परिपत्र :-**
 - (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कालित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।

- (ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:-
 - (अ) नकद रसीद द्वारा या
 - (ब) नकद- शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप- 103- प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई-ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या
 - (स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।

7. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-

- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए बोली में अंकित कुल अनुमानित राशि की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं 500/-रुपये राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:-
 - (क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
 - (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
 - (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
 - (ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
 - (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
 - (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
 - (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।
- (iv) **कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का रागपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):**— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाएगा:—
 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो
 - (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य निष्पादन राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
- (vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:—
 - (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
 - (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
- (vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

8. बोली लगाने से विवर्जन:-

- (i) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह —
 - (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या
 - (ख) भारतीय दण्ड संहिता 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के किसी अपराध के लिए दोष किया गया है।
 उपर्युक्त के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।
- (ii) किसी बोली लगाने वाले ने आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया गया है तो उपापन संस्था बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।
- (iii) जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन उपापन संस्था द्वारा किसी भी

उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

- (iv) राज्य सरकार या, यथा स्थिति, उपापन संस्था उपर्युक्त शर्त के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नहीं करेगी जब तक की ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

9. **भुगतान:-**

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाइ किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।
- (iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाइ पूर्ण करेगा।

(vi) **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-**


परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मागले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाइ करने में असफल रहा है:-

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%
- (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
- (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%
- (ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाइ को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाइ पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (ज) यदि माल की सप्लाइ करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

10. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

11. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आइटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
13. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
14. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
16. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।


महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder

9

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor
procurement of.....in response to their
Notice inviting Bids No.....Dated.....I/we
..... hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency
in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :



Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **DG & IG Jail Rajasthan, Jaipur.**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary/Additional Chief Secretary Home Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.**

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality+

(5) Form of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.


(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature of bidder



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

Appeal No. of
..... Before
the (First/Second Appellate authority)

- 1- Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
- 2- Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
- 3- Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
- 4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:
- 5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
- 6- Grounds of appeal :
.....
.....
(Supported by an affidavit)
- 7- Prayer.....
.....
.....

Place :

Date :

Appellant's Signature